बढ़ती बेरोजगारी चिंताजनक

अर्थव्यवस्था के अनुपात में रोजगार के अवसरों का नहीं बढ़ना लंबे समय से चिंता का विषय है. इस कारण आर्थिक वृद्धि को 'जॉबलेस ग्रोथ' की संज्ञा भी दी जाती है. लेकिन, कुछ सालों से अनेक आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है. आर्थिक परिदृश्य पर नजर रखनेवाली भरोसेमंद संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में बेरोजगारी दर बीते 27 महीनों में सबसे ज्यादा रही, जब यह दर 7.38 फीसदी तक जा पहुंची. सितंबर, 2016 में यह दर 8.46 फीसदी थी. इस कारण 2018 में रोजगार में लगे लोगों की संख्या में 1.09 करोड़ की कमी दर्ज की गयी है. बेरोजगारी बढ़ने के साथ श्रम भागीदारी दर का नीचे आना समस्या को बेहद जटिल बना देता है. यह दर श्रम शक्ति (15-64 साल की आयु के लोगों की कुल संख्या) में काम करने के इच्छुक लोगों तथा रोजगार में लगे या रोजगार पाने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के अनुपात को इंगित करती है. दिसंबर, 2017 और दिसंबर, 2018 के बीच इसमें 1.10 फीसदी का अंतर है. इसका मतलब यह है कि घटते अवसरों की वजह से निराश लोग रोजगार की ओर उन्मुख नहीं हैं. श्रम भागीदारी दर में कमी आम तौर पर अर्थव्यवस्था में संकुचन या मंदी का एक संकेत होती है. इस रिपोर्ट की एक अन्य अहम बात यह है कि 2018 में रोजगार में जो कमी आयी है, उसका 83 फीसदी से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध है. इस आंकड़े को कृषि संकट के साथ रखकर देखें, तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि गांव-देहात की आर्थिकी बेहद खराब दशा में है. उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग हमारे उद्योगों के लिए बड़ा सहारा है, परंतु खेती की मुश्किलों और रोजगार की कमी से इस मांग पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. एक निराशाजनक आंकड़ा यह भी है कि एक करोड़ से अधिक अवसरों की कमी की गाज सबसे अधिक महिलाओं पर गिरी है. साल 2018 में 88 लाख महिलाओं ने काम का मौका खोया, जिनमें 65 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में बसती हैं. कामकाजी लोगों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाये बिना आर्थिक और सामाजिक विकास को सुदृढ़ आधार दे पाना बहुत मुश्किल है. रोजगार पर चर्चा करते समय कुछ खास पहलुओं का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए. हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा है कि रोजगार और काम में अंतर होता है. नीति आयोग समेत अनेक संस्थाएं और अर्थशास्त्री अल्प रोजगार को भी समस्या का हिस्सा मानते हैं. अनेक कामगार या तो अपनी क्षमता से कमतर काम कर रहे हैं या स्थायी या निश्चित अवधि के लिए नहीं हैं. अक्सर काम के एवज में मिलनेवाला वेतन-भत्ता कम होता है तथा उसके साथ बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं नहीं होती हैं. ऐसी स्थिति में सरकार और उद्योग जगत को दूरगामी प्रयासों पर विचार करना चाहिए.

एक निराशाजनक आंकड़ा यह भी है कि एक करोड़ से अधिक अवसरों की कमी की गाज सबसे अधिक महिलाओं पर गिरी है.

तय होती है सुधारों की जीत

आकार पटेल
कार्यकारी निदेशक,
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया
aakar.patel@gmail.com

वर्ष 2016 में केरल में हुए विधानसभा चुनावों के फलस्वरूप वहां वाम मोर्चे की सरकार बनी. कांग्रेसनीत मोर्चे की पराजय हुई और उसके सात प्रतिशत मत उसके पाले से खिसक गये. यही नहीं, वाम मोर्चे की विजय के बावजूद उसके मतों में भी दो प्रतिशत की गिरावट आ गयी. दरअसल, मतों के ये हिस्से इन दो मोर्चों के समर्थन से खिसक कर जिस एक पार्टी के समर्थन में जा पड़े, वह भारतीय जनता पार्टी थी, मलयाली मतों में जिसकी पूर्ववर्ती 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़ कर तब 15 प्रतिशत पर पहुंच गयी.

यों तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक ऊंची और उत्साहवर्धक बढ़ोतरी थी, पर पार्टी कई दशकों से पूरे देश में ऐसी ही उपलब्धि हासिल कर रही थी. गुजरात में जन संघ (भाजपा का पिछला स्वरूप) द्वारा 1970 के दशक के मध्य तक केवल दो से तीन प्रतिशत मत हासिल किये जाने पर भी पार्टी नेतृत्व बगैर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के संगठन खड़ा करने में लगा रहा. उसके बाद तो फिर इमरजेंसी एवं अयोध्या आंदोलन के रूप में जैसे ही उसे जन समर्थन का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसने उसे लपक लिया.

कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक एवं विभाजनकारी मुद्दों का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने का आरोप आसानी से लगा सकता है, लेकिन, उसे उसमें विफल होने का दोषी नहीं बता सकता. किंतु केरल में पार्टी द्वारा प्राप्त की गयी यह उपलब्धि अपने साथ हिंसक वारदातों की बाढ़ लेकर आयी. वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), भारतीय जनता पार्टी एवं वाम दलों के बहुत-से समर्थक मारे गये हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अपना-अपना दबदबा कायम करने के लिए छिड़े संघर्ष ने अत्यंत बुरा रूप हासिल कर लिया है. राज्य विधानसभा के लिए वर्ष 2016 में संपन्न इन चुनावों में यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक सीट पर विजय हासिल की, पर अगले चुनावों तक वह खुद के लिए इतना समर्थन हासिल कर चुकी होगी कि उनके नतीजे में यह पार्टी इस राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में स्थापित हो जायेगी.

पार्टी द्वारा सबरीमला मुद्दे के आक्रामक इस्तेमाल ने इसे अगड़ी जातियों के अच्छे-खासे मत प्रतिशत का समर्थन आकृष्ट करने में सहायता पहुंचायी है. ये अगड़ी जातियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला मंदिर में सभी भारतीयों के अबाधित प्रवेश के हक में फैसला सुनाये जाने से खार खायी बैठी हैं. यह दूसरी बात है कि इस सवाल पर अंतिम विजय महिलाओं तथा उन लोगों की ही होगी, जो पारंपरिक अधिकारों पर व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन किया करते हैं. उनकी इस जीत का दूरगामी प्रभाव यह होगा कि समाज और राजनीति में सुधारकों का असर बढ़ेगा. हालिया विवाद से पहले जब तक किसी भी महिला को वहां पूजा-अर्चना की अनुमति नहीं थी, एक भावनात्मक शक्ति ने इस मुद्दे को ज्वलंत बनाये रखा था. मगर जैसे-जैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मंदिर में प्रविष्ट होकर दर्शन-पूजन करने लगेंगी, यह मुद्दा धीरे-धीरे धूमिल पड़ता चला जायेगा.

समाज के रूढ़िवादी तत्व सुधारों को हमेशा स्थगित रखना चाहते हैं. जब ये तत्व दलितों के मंदिर प्रवेश पर पराजित होते हैं, तब वे महिलाओं के मंदिर प्रवेश जैसे किसी दूसरे मुद्दे पर स्थानांतरित हो जाते हैं.

हम भारत में ऐसे ही एक अन्य मुद्दे पर इसी तरह के घटनाक्रम का अवलोकन कर चुके हैं, जब साल 1930 के दशक में दलितों के मंदिर प्रवेश के समर्थन पर दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने महात्मा गांधी का विरोध करते हुए उनके विरुद्ध धरने का भी आयोजन कर डाला था. तब अहमदाबाद में तो यहां तक हुआ कि मेरे खुद के समुदाय के पटेलों ने दलितों को मंदिरों से बाहर रखने के उद्देश्य से स्वयं को गैर हिंदू घोषित कर दिया, ताकि वे बंबई हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम के स्वयं पर लागू न होने का दावा कर सकें. पर जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह की चीजें बहुत अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती हैं. आखिरकार, हम परंपरा-पोषण के नाम पर भेदभाव बरकरार नहीं रख सकते और एक अरसे में तो हमेशा ही सही चीजें मान्यता प्राप्त कर ही लेती हैं.

मंदिरों में दलितों के प्रवेश के विरुद्ध पटेलों ने भी अपना संघर्ष जारी रखते हुए जल्दी हार स्वीकार न की. पर अंततः वे सुप्रीम कोर्ट में यह केस हार ही गये. अपना फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि 'मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का अधिकार उनके द्वारा सभी सामाजिक सुविधाएं तथा अधिकार पाने का प्रतीक है, क्योंकि सामाजिक न्याय उस लोकतांत्रिक जीवनशैली का मुख्य आधार है, जो भारतीय संविधान के प्रावधानों में निहित है.' आज इस कथन में वर्णित विचार सामान्य वास्तविकता का बोध कराते जैसे लगते हैं और कोई भी इनसे छूट पाने की बात सोच भी नहीं सकता.

केरल में भी ऐसा ही कुछ घटित होगा, जब कुछ ही महीनों अथवा वर्षों के बाद महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश सामान्य-सी बात बन चुकी होगी. जो लोग अभी एक परंपरा पर चोट पहुंचने से नाराज और क्षुब्ध हैं, एक अरसे के बाद वे अपना क्रोध भूल चुके होंगे. जो लोग कभी दलितों को मंदिर से बाहर रखना चाहते थे, वे अब कहीं खोजे से भी नहीं मिल सकते. दरअसल, आज वे कहीं गायब नहीं हो गये हैं. जो हुआ, वह यह कि अब उनके विचार बदल चुके हैं और हमारा समाज भी बदल चुका है. वर्तमान में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि व्यक्तिगत अधिकारों पर परंपरा को तरजीह देते हुए दलितों को मदिरों से बाहर रखा जाना चाहिए. इसी तरह, एक अवधि के बाद हमें इस बात पर हैरत होगी कि वर्ष 2019 में हम महिलाओं के मंदिर में प्रवेश जैसे बेकार के मुद्दे पर संघर्ष में लगे थे.

समाज के रूढ़िवादी तत्व सुधारों को हमेशा स्थगित रखना चाहते हैं, क्योंकि सुधार प्रकृति से ही परंपराओं पर चोट करते हैं. जब ये तत्व दलितों के मंदिर प्रवेश पर पराजित होते हैं, तब वे महिलाओं के मंदिर प्रवेश जैसे किसी दूसरे मुद्दे पर स्थानांतरित हो जाते हैं. और इसी तरह भविष्य में भी वे ऐसा ही कोई और मुद्दा उठाकर उस पर संघर्षरत होते हुए एक बार पुनः अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे. लेकिन, अंततः होगा यही कि जो कुछ अवश्यंभावी है, वे उसको स्वीकार कर लेंगे. इस अर्थ में परंपरा की ऐसी हार अल्पावधि में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचायेगी. मगर, कानून का पालन तथा अधिकारों का सम्मान करनेवाले समाज के रूप में यह हमारे लिए दीर्घावधि में फायदेमंद ही सिद्ध होगी.

इस साल बढ़ेगा जीडीपी का आकार

डॉ जयंतीलाल भंडारी
अर्थशास्त्री
jlbhandari@gmail.com

विभिन्न आर्थिक चुनौतियों के बीच 2018 की तुलना में 2019 में भारत की जीडीपी का आकार बढ़ेगा. परिणामस्वरूप भारत की संभावित विकास दर भी 7.5 फीसदी से अधिक होगी. साथ ही दुनिया के परिदृश्य पर 2019 में भी भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर 50 डॉलर प्रति बैरल हो जाने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होगा. साथ ही वर्ष 2019 में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिये जानेवाले आर्थिक प्रोत्साहनों तथा उनके हितों के लिए विभिन्न नयी योजनाओं से भी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा.

यकीनन नये वर्ष 2019 में देश की अर्थव्यवस्था में कर सुधारों का नया परिदृश्य दिखायी देने की संभावनाएं हैं. टैक्स रिफंड के लिए मैन्युअल रिकॉर्ड और प्रक्रिया की बड़ी खामी को दूर किया जायेगा. वास्तविक व्यवहार में आ रही जीएसटी दरों से संबंधित कई उलझनों का निराकरण किया जायेगा और जीएसटी पोर्टल को अधिक सक्षम बनाया जायेगा. जीएसटी की एकल मानक दर लागू होगी और एक विवरणी दाखिल करने की सुविधा भी होगी. निस्संदेह इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा. इसमें कोई दो मत नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. वैश्विक संगठनों ने कहा कि आर्थिक विकास दर सुस्त रहने की एक प्रमुख वजह जीएसटी का लागू होना है. यद्यपि विकास दर में कमी जीएसटी के पहले भी आनी शुरू हो गयी थी, लेकिन जीएसटी ने इसमें तेजी ला दी. सरल जीएसटी के कारण देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति से आगे बढ़ेगी.

किसानों की कर्जमाफी और किसानों के लिए विभिन्न उपहारों की संभावनाओं से इस वर्ष कृषि और किसानों की खुशहाली दिखायी देगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी के वचन से कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद अन्य प्रदेशों की सरकारों और केंद्र की मोदी सरकार पर भी किसानों के कर्ज को माफ करने का दबाव बना है. नीति आयोग द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए इस साल जो न्यू इंडिया रणनीति जारी की गयी है, उसके कार्यान्वयन से भी कृषि और किसान लाभान्वित होंगे. निश्चित ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को नरम करने, अनुबंधित खेती को बढ़ावा देने, बेहतर मूल्य के लिए वायदा कारोबार को प्रोत्साहन देने, कृषि उपज की नीलामी के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीति को बढ़ाये जाने से कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

नयी कृषि निर्यात नीति के तहत कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर के मूल्य से बढ़ा कर 2022 तक 60 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने और भारत को कृषि निर्यात से संबंधित दुनिया के 10 प्रमुख देशों में शामिल कराने का लक्ष्य है. नयी कृषि निर्यात नीति में खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, दूध, चाय, कॉफी जैसी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने और कृषि उत्पादों के ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस है. इसके अलावा कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने, प्रोडक्ट के मानक तय करने जैसे कदम भी बताये गये हैं. निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष क्षेत्र बनाये जायेंगे और बंदरगाहों पर विशेष व्यवस्था की जायेगी. इनके लिए सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया है. यद्यपि कृषि निर्यात को आगामी चार वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत में कृषि निर्यात की विभिन्न अनुकूलताओं के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) की भी नयी संभावनाएं आकार ग्रहण करेंगी.

पिछले वर्ष (2018 में) लिये गये कई प्रमुख आर्थिक निर्णयों से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और जीडीपी बढ़ेगी. देश के विकास में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के महत्व को देखते हुए इसे बढ़ावा देने और इसे अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से 'सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग' में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति ऑटोमैटिक रूट के जरिये दी गयी है, वह रिटेल ट्रेडिंग बढ़ाने में लाभप्रद होगी. यद्यपि वर्ष 2019 में वैश्विक शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में कॉरपोरेट आमदनी, सार्वजनिक निवेश और विदेशी निवेश भी बढ़ने की संभावना है. आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय शेयर बाजार में उम्मीद का माहौल रहेगा.

इस साल उद्योग-कारोबार के लिए जीएसटी को और सरल बनाना होगा. बेनामी संपत्ति पर जोरदार चोट करनी होगी. अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की रफ्तार तेज करना होगी. वैश्विक संरक्षणवाद की नयी चुनौतियों के बीच सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने होंगे. निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे देशों के बाजार भी जोड़े जाने होंगे, जहां गिरावट अधिक नहीं है. सरकार के द्वारा भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनानेवाले सूक्ष्म आर्थिक सुधारों को लागू किया जाना होगा. अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अहम भूमिका बनानी होगी. मेक इन इंडिया योजना को गतिशील करना होगा. उन ढांचागत सुधारों पर जोर देना होगा, जिसमें निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके. इससे भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नयी संभावनाएं आकार ले सकती हैं. हम आशा करें कि वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था भी चमकीली बनेगी.

पिछले वर्ष लिये गये कई प्रमुख आर्थिक निर्णयों से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और जीडीपी बढ़ेगी. इस साल भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नयी संभावनाएं आकार ले सकती हैं.

बोधि वृक्ष

संकल्प

दो विचारधाराएं हैं. एक विचारधारा के अनुसार, आप अपना लक्ष्य रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं. दूसरी विचारधारा के अनुसार, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर जो करेगा, वह आपकी बेहतरी के लिए ही होगा, आप सब कुछ ईश्वर पर समर्पण कर देते हैं. यह दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी लगती हैं पर मेरे अनुसार ऐसा नहीं है. संकल्प या लक्ष्य रखना अच्छा है, लेकिन चौबीस घंटे हम उसी के बारे में नहीं सोचते रहते हैं. बिना किसी ज्वर के उसके लिए कार्यरत रहते हुए उसको ईश्वर पर छोड़ देते हैं. इन दोनों विचारधाराओं के जोड़ से ही काम होगा. हमारे वेदों में इसको बड़ा सुंदर बताया गया है- संकल्प लेकर और उसके लिए कार्यरत रहते हुए उसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं- 'मुझे यह चाहिए और आप मुझसे बेहतर जानते हैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है'- यह या इससे बेहतर. कई बार आप जानते ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए. अगर आप सच में जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उसे पाना कोई मुश्किल ही नहीं है. बहुत से समय तो हम अनिश्चित होते हैं. कई बार जब आप किसी वस्तु के लिए लगातार कुछ प्रयत्न करते हैं, तो आप पाते हैं कि अगले सप्ताह, या फिर अगले महीने या फिर अगले साल आपको वह नहीं चाहिए होता है. इसलिए कुछ संकल्प करने से पहले अपनी सजगता बढ़ानी चाहिए. इस ब्रह्मांड में अपना संकल्प डालो- मुझे यह चाहिए या इससे बेहतर. अब प्रश्न यह है कि एक इच्छा और संकल्प में क्या भेद है? मान लो तुम्हें बेंगलुरु से मुंबई जाना है. तुम टिकट खरीदते हो और तीन घंटे का सफर तय करके मुंबई जाते हो. पर, अगर तुम इस सारे समय में मन में यही दोहराते रहो कि तुम्हें मुंबई जाना है और तुम मुंबई जा रहे हो, तो हो सकता है कि तुम कहीं और ही पहुंच जाओ! जब संकल्प के साथ ज्वर जुड़ जाता है, तो वह इच्छा है. बिना ज्वर की इच्छा संकल्प है. और फिर उसके लिए कार्यरत रहते हुए यह विश्वास की जो भी प्रकृति तुम्हें दे रही है, वह तुम्हारे विकास के लिए ही है.

श्रीश्री रविशंकर

आपके पत्र

शायद काम करे यह दबाव

सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजग सरकार की उनके खिलाफ सीबीआइ जांच उनकी छवि को खराब करने की राजनीति है, जिससे वह तनिक भी डरने वाले नहीं हैं, मगर राजनीति में कहा तो बहुत कुछ जाता है, होता कुछ और ही है. दूसरी ओर ऐसी ही बातें कांग्रेस भी अपने खिलाफ हो रही सीबीआइ जांचों पर पहले ही कह चुकी है. ऐसे दबाव और डर को देख कर ये लोग अब अपनी अकड़ छोड़ कर और कुछ नरमी के साथ एक भी हो सकते हैं. साथ ही वर्तमान कमजोर गठबंधन को कुछ और मजबूत बना सकते हैं. एक कहावत भी है कि पीड़ित लोग समय आने पर अपने बड़े विरोधी को घेरने और दबाने के लिए जल्द एक हो जाते हैं.

वेद मामूरपुर, नरेला

वैश्विक शांति की राह में रोड़ा

चीन और अमेरिका के बीच बाजार से शुरू हुई तनातनी अब एक दूसरे को नीचा दिखाने तक आ गयी है. गुरुवार को जहां चीन ने चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह पर स्पेसक्राफ्ट चांग-4 उतार कर इतिहास रचा, वहीं अब उसने सबसे पावरफुल बम बनाने का दावा किया है. चीन का दावा है कि यह परमाणु हथियारों के बाद का दूसरा सबसे ज्यादा घातक हथियार हैं और इससे होने वाली तबाही लगभग परमाणु बम जैसी ही होगी. चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी का लंबा दौर अब हथियारों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जो कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है. इसका दुष्परिणाम केवल अमेरिका और चीन को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को उठाना होगा. गौरतलब है कि चीन कई वर्षों से साम्राज्यवादी मंसूबे पर काम कर रहा है और पूरी दुनिया इसे समझ कर उसका विरोध भी कर रही है. हथियारों की होड़ का वैश्विक विरोध होना चाहिए.

अमन सिंह, प्रेमनगर, बरेली

स्थानीयता का जिन्न

बेरोजगारी देश की एक बड़ी समस्या है. इसका समाधान ढूढ़ने में असमर्थ सरकारें नये-नये जुमले गढ़ कर नौजवानों को भटकाती रही हैं. नौजवानों को तरह-तरह के सपने दिखाये जाते हैं, तो कभी सियासत की बोतल से स्थानीयता का जिन्न निकल आता है. कर्ज के बाजार से निकला रोजगार युवाओं को तरक्की के हाइवे पर ले जायेगा या कर्ज के दलदल में फंसा देगा, कहा नहीं जा सकता. कुछ होनहार युवा विदेशों का रुख कर लेते हैं, तो ज्यादातर सड़कों पर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं. मौका देख सियासत बिना देरी किये 'बाहरियों ' का हौवा और 'प्रतिशत' का हिसाब बता कर बेरोजगारों को बरगलाने में जुट जाती हैं. मसला चाहे मराठी मानुष का हो या यूपी-बिहार में घुसपैठ का, भौंहें तो दिल्ली से असम तक की तन जातीं हैं. प्रदेश चाहे उत्तर हो या मध्य, राजनीतिक झांसों के तरीके सबके एक जैसे हैं. बहरहाल, इस समस्या के मर्म को समझते हुए सरकारी संरक्षण में आकर्षक रोजगार पैदा करने होंगे, वरना वर्तमान पीढ़ी भविष्य के लिए कर्जदार बन कर रह जायेगी.

एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू, रांची

कुछ अलग

उम्मीद की किरण नयी हिंदी

सन्नी कुमार
टिप्पणीकार
sunnyand65@gmail.com

मानव जाति ने हमेशा से स्वयं को किसी न किसी तरह अभिव्यक्त किया है. समय के साथ अभिव्यक्ति के साधन और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया, इसलिए हर युग की कला अपने स्वरूप, उद्देश्य, रचना इत्यादि में स्वाभाविक भिन्नता रखती है. वर्तमान समय में 'नयी हिंदी' को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए.

जिसे हम नयी वाली हिंदी कहते हैं, उसने न केवल नये युवा लेखकों की पौध तैयार की है, बल्कि एकदम नया और विस्तृत पाठकवर्ग भी तैयार किया है. यह हिंदी के लिए गर्व की बात है. आज वृहद रूप से स्कूल-कॉलेज के छात्रों तथा युवा पेशेवर पाठकों का इसी नयी हिंदी के माध्यम से पहली बार साहित्य पठन-पाठन के क्षेत्र में प्रवेश हुआ है, जो निश्चित ही समय के साथ अन्य विधाओं में भी रुचि लेगा. जो लोग भाषा-व्याकरण को लेकर पवित्रता की हद तक कट्टर हैं, उन्हें मानना पड़ेगा कि उनका यह आग्रह भाषा विस्तार में बाधक है. भाषाई नियमों का पालन किया जाना चाहिए, किंतु ये नियम साहित्य सृजन के साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं. नये शब्दों का प्रयोग या फिर जिसे उपहासपूर्ण ढंग से 'मिक्स्ड भाषा' कहा जाता है, वह दरअसल इस समय के एक बड़े पाठक समूह की भाषा है, जिससे जुड़ने के लिए उनकी भाषा का ही प्रयोग करना होगा.

नयी हिंदी इस अर्थ में भी उत्साह पैदा करती है कि इसमें पर्याप्त विविधता है और यह समाज के अलग-अलग क्षेत्रों की कहानी कह रहा है. 'बनारस टॉकीज' जहां विश्वविद्यालय कैंपस के छात्रों की कहानी कहता है, तो वहीं 'पतनशील पत्नियों के नोट्स' नारी विमर्श में एक सशक्त हस्तक्षेप है. इसी प्रकार 'रेखना मेरी जान' उपन्यास के मूल में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण परिवर्तन है. ऐसे अनेक उदाहरण गिनाये जा सकते हैं.

नयी हिंदी पर लगनेवाला आक्षेप कि यह केवल लोकप्रियता को आधार मानता है और गंभीर लेखन से दूर है, इसके संबंध में इस दिलचस्प तथ्य का उल्लेख जरूरी होगा कि 'डार्क हॉर्स' जहां सबसे अधिक बिकनेवाली शीर्ष किताबों में रही, तो इसे 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' के रूप में गंभीरता का प्रमाणपत्र भी मिला. हमें इस सोच से आजाद होना पड़ेगा कि जो लोकप्रिय है, वह गंभीर नहीं है. वहीं लेखकों की सोशल मीडिया पर उपस्थिति एक सुखद संकेत है. इससे वर्चुअल माध्यम बौद्धिक रूप से सशक्त भी होता है और इससे एक वैचारिक पारदर्शिता भी निर्मित होती है. साथ ही प्रकाशकों पर भी एक दबाव होता है कि वे लेखक-पाठक को भी किसी किताब की बिक्री का ठीक-ठीक लेखा-जोखा बतायें. यह एक क्रांतिकारी बदलाव है.

हिंदी को इस थकाऊ विवाद से बचते हुए 'लेखक-प्रकाशक कॉन्ट्रैक्ट', 'ई- बुक पब्लिकेशन' इत्यादि जैसे विषयों पर ध्यान लगाना चाहिए. इससे न केवल भाषा का प्रसार होगा, बल्कि लेखकों की आय भी बढ़ेगी. भूखे पेट हिंदी की व्यथा कहने से बेहतर है, भरे पेट से हिंदी के विस्तार की बात सोची जाये. नयी वाली हिंदी इस संबंध में बड़ी उम्मीद जगाती है.

देश दुनिया से

गैबॉन में सैनिकों ने की तख्तापलट की कोशिश

मध्य आफ्रीकी देश गैबॉन की सेना ने बीमार राष्ट्रपति अली बोंगो के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की. सात जनवरी की सुबह एक सैनिक ने राष्ट्रीय टीवी पर एक संदेश के जरिये घोषणा की थी कि देश में लोकतंत्र बहाली के लिए सेना ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया है. राष्ट्रीय रेडियो पर एक अलग संदेश में सैन्य अधिकारियों ने स्ट्रोक के बाद मोरक्को में स्वास्थ्य लाभ ले रहे बोंगो के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया. सेना ने स्थानीय समयानुसार चार बज कर 30 मिनट पर रेडियो संदेश और उसके थोड़ी ही देर बाद टीवी पर संदेश प्रसारित किया. एक सूत्र ने कहा कि टीवी स्टेशन के बाहर गोलीबारी हुई थी, लेकिन षड्यंत्रकारी सैनिकों के एक छोटे समूह के रूप में उपस्थित हुए थे. राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि वे बहुत जल्द इस संबंध में एक बयान देंगे. विदित हो कि 59 वर्षीय बोंगो स्ट्रोक आने के बाद अक्तूबर से ही सऊदी अरब के अस्पताल में भर्ती थे. नवंबर से वे मोरक्को में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं. नये वर्ष के अपने भाषण में बोंगो ने कहा था कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा है. बीते लगभग आधे दशक से बोंगो परिवार इस देश पर शासन कर रहा है. बोंगो से पहले उनके पिता ओमर इस देश के राष्ट्रपति थे.

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है